

शाह का जीरो टेरर प्लान

आतंकवाद के इकोसिस्टम पर प्रहार से उखड़ने लगी दहशतगर्दी की सांस

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए जीरो टेरर प्लान तैयार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भरोसा है कि इसके जरिए 2026 तक जम्मू-कश्मीर से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंका जाएगा। शाह ने कहा कि पहले सिर्फ आतंकवादियों को मारा जाना था, लेकिन अब इसके पूरे इकोसिस्टम को खत्म किया जा रहा है। जीरो टेरर प्लान के तहत ही कम्प्लॉट एरिया डॉमिनेशन प्लान बनाया गया है। वह 2023 का समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा करता है। ही तो सारे माह में वे स्वयं वहाँ जाकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हैं। 2010 में जम्मू-कश्मीर में 2,654 पथराव की घटनाएं हुई थीं, जबकि 2019 में 1,644 पथराव की घटनाएं हुई थीं।

केंद्रीय गृह एवं सशक्तिकारी अमित शाह ने बधावार को लोकसभा में जम्मू और कश्मीर अरक्षण (संशोधन) विधेयक

2023 व जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर

इकोसिस्टम

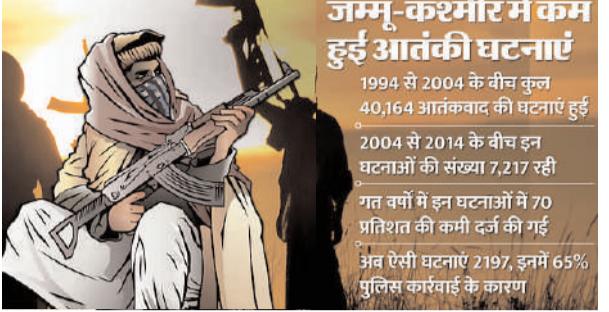
“शाह ने कहा कि पहले सिर्फ आतंकवादियों को मारा जाता था, लेकिन अब इसके पूरे इकोसिस्टम को खत्म किया जा रहा है।

चर्चा का जबाब देते हुए यह बताते हैं। आतंकवाद के मूल मौजूदा की समीक्षा करता है। ही तो सारे माह में वे स्वयं वहाँ जाकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हैं। 2010 में जम्मू-कश्मीर में 2,654 पथराव की घटनाएं हुई थीं, जबकि 2019 में 1,644 पथराव की घटनाएं हुई थीं।

केंद्रीय गृह एवं सशक्तिकारी अमित शाह ने बधावार को लोकसभा में जम्मू और कश्मीर अरक्षण (संशोधन) विधेयक

प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। अब ही 2010 में 132 ऑर्जेनाइज्ड ऐसे घटनाएं 2,197 रह गई हैं। इन

हड़ताले हुई थीं, जबकि 2023 में



जम्मू-कश्मीर में कम हुई आतंकी घटनाएं

1994 से 2004 के बीच कुल 40,164 आतंकवादी की घटनाएं हुईं।

2004 से 2014 के बीच इन घटनाओं की संख्या 7,217 रही।

गत वर्षों में इन घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी की गई।

अब ऐसी घटनाएं 2197, इनमें 65% पुलिस कार्रवाई के कारण।

घटनाओं में से 65 प्रतिशत, पुलिस कार्रवाई के कारण घटित हुई थीं।

2023 में एक भी पथराव की घटना नहीं।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, 9 वर्षों में नारियों की मृत्यु की संख्या में 72 प्रतिशत और सुरक्षालोगों की मृत्यु की संख्या में 59 प्रतिशत की कमी आई है। साल 2010 में जम्मू और कश्मीर में 2,654 पथराव की घटनाएं हुई थीं, जबकि 2023 में पथराव की एक भी घटना नहीं हुई है।

2004 से 2014 के बीच कुल 40,164 आतंकवादी की घटनाएं हुई थीं।

2004 से 2014 के बीच कुल 7,217 रही।

गत वर्षों में इन घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी की गई।

अब ऐसी घटनाएं 2197, इनमें 65%

पुलिस कार्रवाई के कारण।

2010 में युसपैट की 489 घटनाएं हुई थीं। 2023 में सिर्फ 48 घटनाएं हुई हैं।

अब इकोसिस्टम को खत्म करने पर जोर

शाह के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में जीरो टेरर प्लान बनाया गया है।

इस पर पिछले तीन वर्षों से अमल हो रहा है। 2026 तक यह जीरो टेरर प्लान पूरी तरह से अमल में आ जाएगा। इकोसिस्टम को खत्म किया जा रहा है।

पहले सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने के बाबत यात्रा बढ़ा रखी गयी।

वहाँ तक यह जीरो टेरर प्लान बनाया गया है। अब इसके पूरे इकोसिस्टम को खत्म किया जा रहा है।

एक भी नहीं हुई। 2010 में पथराव में 112 नारियों की मृत्यु हुई थी, जबकि 2023 में एक भी नहीं हुई।

2010 में पथराव में 6,235 सुरक्षा कर्मी घायल हुए थे, 2023 में एक भी नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में इस प्रतिशत की मदद के कारण व्यापक व्यापार की व्यवस्था की है कि वहाँ पर अब एक कंकड़ फेंकने की भी हिम्मत नहीं हो रही।

साल 2010 में सौजन्यात्मक घटनाएं 7,217 रहीं। जबकि 2023 में 83 केस दर्ज किए गए हैं।

एक भी नहीं हुई।

2010 में पथराव की मृत्यु की संख्या 40,164 रही।

जबकि 2023 में 7,217 रही।

एक भी नहीं हुई।

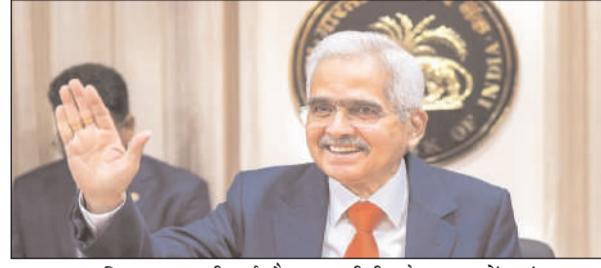
एक भी नही

एमपीसी ने रेपो एट को 6.5 प्रतिशत पर बढ़ाकर दखा आरबीआई गवर्नर ने की मौद्रिक नीति की घोषणा

अर्थव्यवस्था

“वैश्विक अनिष्टिता के माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है।

आरबीआई एमपीसी ने एक बार फिर रेपो रेटों को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। एमपीसी की बैंक के बार आरबीआई गवर्नर ने बताया कि वैश्विक अनिष्टिता के माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। बैंक के बैलेस शीर्ष में मजबूती दिखाई है। केंद्रीय बैंक की एमपीसी ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार इसके फलस्वरूप स्थायी जमा सुधारा दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुधारा दर तथा बैंक



दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने FY24 में जीडीपी ग्रोथ 7 फीसदी रहने का बताया है।

एमपीसी की बैंक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि चेलू मांग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी जारी है। लगात खर्च में कामी से विनियोग क्षेत्र में मजबूती आई है। FY 24 के सीधीपी 5.4 प्रतिशत पर बने रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महाराष्ट्र दर चार प्रतिशत पर लाने के प्रति

एमपीसी के छह में पांच स्पर्ध अकोमेडेटर खुला वापस लेने के लिए रेपो रेट को स्थिर रखने पर सहमति जताई।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नवंबर-दिसंबर महीने में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़द महाराष्ट्र के मांग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी जारी है। लगात खर्च में कामी से विनियोग क्षेत्र में मजबूती आई है। केंद्रीय बैंक की एमपीसी ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार इसके फलस्वरूप स्थायी जमा सुधारा दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुधारा दर तथा बैंक

गेहूं की जमाखोरी को रोकने के लिए उठाया कदम

अंकुश

“खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि कमी को रोकने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा किया गया है।



रिटेलर पर स्टॉक सीमा 10 टन से बजाए पांच टन, बड़े चेन रिटेलर के प्रत्येक डिपो के लिए 5 टन और सभी दियों के लिए कुल एक हजार टन होगी। उहोंने कहा कि प्रोसेसर के मामले में वे मासिक स्थिति क्षमता का 70 प्रतिशत 2023-24 के शेष महीनों से गुण करके रख सकते हैं।

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि कमी को रोकें और उत्तराखण्ड की खिलाफ वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत वित्त तंडलक कार्रवाई की जाएगी। 12 जून को खाद्य मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के व्यापारियों पर मार्च 2024 तक स्टॉक रखने की संशोधित सीमा तक कम करने के लिए 30 दिन का समय

मिलागा। अधिकारिक बयान में कहा गया कि सभी गेहूं स्टॉकिंग संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंसीकरण करना होगा। साथ ही हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति को अपडेट करनी होगी।

यदि कोई भी संस्था, जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत वित्त तंडलक कार्रवाई की जाएगी।

इस साल मई में अनाज की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य नियम (एक्सीआई) को गेहूं

नहीं दिल्ली। सरकार जनवरी से मार्च के दौरान एमएसएस के तहत एक्सीआई का 2.5 मिलियन टन अतिरिक्त गेहूं उत्तराखें को तैयार है। सरकार खुले बाजार बिक्री योजना (ओप्पारसास) के तहत शेक्षण उपभोक्ताओं को एक्सीआई का 2.5 मिलियन टन अतिरिक्त गेहूं बेचने का एलान कर दिया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को यह जनवरी दी।

इस साल मई में अनाज की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य नियम (एक्सीआई) को गेहूं उत्तराखें को खरीद या बेचने का अधिकारिक अधिकारिक अधिसूचना आठ अनुमति दी जाएगी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक बड़ा अंकुश लगाने के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को तत्काल प्रभाव से और समाप्त कर दिए गए हैं।

साथ ही उहोंने बताया कि थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी जाएगी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक बड़ा अंकुश लगाने और खेती-प्रसंगीनों को अनुमति दी जाएगी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी जाएगी।

भारत ने पांच और देशों को गैर बासमती चावल के नियात की अनुमति दी, आधिकारिक अधिसूचना जारी

नहीं दिल्ली। घेरू कीमतों पर

गेहूं-बासमती सफेद चावल के नियात की अनुमति दी दी गई।

बता दें कि घेरू कीमतों पर

अंकुश लगाने और घेरू खाद्य सुरक्षा सुनियोग करने के लिए

गेहूं-बासमती सफेद चावल के नियात की अनुमति दी गई थी।

बता दें कि घेरू कीमतों पर

अंकुश लगाने और घेरू खाद्य सुरक्षा सुनियोग करने के लिए

गेहूं-बासमती सफेद चावल के नियात की अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखने के नियमों को अनुमति दी गई थी।

गेहूं सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वितरण के लिए एक स्टॉक रखन

